भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3008

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

20 फाल्गुन, 1947 (शक)

तिरूनेलवेली में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

3008. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मांग किए जाने पर सभी ग्राम पंचायतों और उससे आगे भी ब्रॉडबैंड संपर्क प्रदान करने के लिए तिरुनेलवेली जिले में भारतनेट परियोजना कार्यान्वित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर ई-गवर्नेंस सेवाओं, डिजिटल साक्षरता और नागरिक सहभागिता के संदर्भ में तिरूनेलवेली में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की स्थिति क्या है;

(ग) ग्राम पंचायत स्तर पर टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन, एलईडी लाइटिंग, वाई-फाई हॉटस्पॉट और कौशल विकास जैसी सेवाओं की उपलब्धता के मद्देनजर तिरूनेलवेली में डिजिटल ग्राम पहल की प्रगति क्या है;

(घ) तिरूनेलवेली के पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना स्थापित करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए तिरूनेलवेली में डिजिटल संपर्क और अवसंरचना को बढ़ावा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था।

समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार करें, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें और भारत में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करें।

भारतनेट

इसे दूरसंचार विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाता है ताकि तमिलनाडु सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके।

इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंच को सक्षम करना और डिजिटल सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करना है। अब तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत कुल 2,14,921 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है, जिसमें तिरुनेलवेली जिले में 113 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

पिछले एक दशक में, तमिलनाडु में डिजिटल कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। यह दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विस्तार, मोबाइल ब्रॉडबैंड की बढ़ती पहुंच और डिजिटल इंडिया, भारतनेट और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जैसी सरकारी पहलों के कारण संभव हुआ है।

इंटरनेट ग्राहकों, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में वृद्धि ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में डिजिटल सेवाओं, डिजिटल भुगतान और ई-गवर्नेंस तक व्यापक पहुंच को सक्षम बनाया है। तमिलनाडु में डिजिटल कनेक्टिविटी की स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	संकेतक	2026 (लगभग)
1	कुल वायरलेस (मोबाइल) ग्राहक	~7.95 करोड़
2	इंटरनेट सब्सक्राइबर	~6.20 करोड़
3	भारतनेट के तहत जुड़ी ग्राम पंचायतें	~10,869+ सेवा-तैयार जीपी
4	मोबाइल कनेक्टिविटी वाले गांव	16,485 गांव
5	सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)	तमिलनाडु (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) में 19,641 सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 13,001 सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्य कर रहे हैं

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने नागरिक-केंद्रित सेवाओं के ऑनलाइन वितरण को सक्षम करने के लिए कई पहल की हैं।

इनमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास और कार्यान्वयन, लाभार्थी की पहचान के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण को बढ़ावा देना और विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से सेवा वितरण का विस्तार शामिल है।

डिजिटल इंडिया पहल मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुलभ है, जिसने शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये पहल नागरिकों को कभी भी और कहीं से भी डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान, ई-कोर्ट आदि जैसी सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकार के पोर्टलों और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ई-गवर्नेंस सेवाओं, डिजिटल साक्षरता और नागरिक जुड़ाव के क्षेत्रों में प्रमुख पहलों की स्थिति निम्नानुसार है, जिसका उद्देश्य सेवा वितरण की दक्षता और गुणवत्ता को बढ़ाते हुए सरकारी सेवाओं तक समावेशी और समान पहुंच सुनिश्चित करना है:

(i) यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग), जो सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन है, प्रचालन में है और व्यक्तियों के लिए **2446+ सेवाएं** (केन्द्रीय 872, राज्य 1,574) प्रदान करता है।

तमिलनाडु राज्य की 422 सेवाएं उमंग प्लेटफॉर्म पर शामिल हैं।

(ii) डिजिलॉकर: डिजीलॉकर ने आम नागरिक के लिए मूल जारीकर्ता से प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक किसी भी समय पहुंच प्रदान की है। डिजिलॉकर की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए **67.56+ करोड़** उपयोगकर्ता इसके साथ पंजीकृत हैं और प्लेटफॉर्म पर 2462 जारीकर्ताओं से 950+ करोड़ दस्तावेज जारी किए गए हैं।

डिजिलॉकर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए तमिलनाडु राज्य में **1.94 करोड़** से अधिक आधार सक्षम पंजीकरण हुए हैं।

(iii) आधार: आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय-आधारित विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है। तमिलनाडु राज्य में 8.47 करोड़ आधार आईडी के साथ अब तक 143.80+ करोड़ आधार आईडी तैयार की गई हैं।

तमिलनाडु में 200+ लोक कल्याण और सुशासन पहल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में लाभार्थी की पहचान के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करती हैं।

(iv) सामान्य सेवा केंद्र सीएससी डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करते हैं जिससे ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में वृद्धि होती है। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

जनवरी, 2026 तक, देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 5.54 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4.32 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्य कर रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुल 444 सीएससी कार्य कर रहे हैं। सीएससी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा https://csc.gov.in/ पर उपलब्ध है और सेवाओं की सूची https://csc.gov.in/ पर उपलब्ध है_।

(v) माईगव: माईगव भारत सरकार का नागरिक सहभागिता मंच है जो कई सरकारी निकायों/मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है। यह नीति निर्माण में लोगों के साथ जुड़ता है और सार्वजनिक हित और कल्याण के मुद्दों/विषयों पर लोगों की राय मांगता है।

वर्तमान में, **6.11+ करोड़** नागरिक माईगव के साथ पंजीकृत हैं, जो माईगव प्लेटफॉर्म पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

राज्य स्तर पर सहभागी शासन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में माईगव स्टेट इंस्टेंस (https://tamilnadu.mygov.in/) भी शुरू किया गया है, जिससे नागरिक अपने विचारों, सुझावों और फीडबैक को सीधे राज्य सरकार के साथ साझा करके सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकें।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) तमिलनाडु सहित देश भर में उभरते और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उद्योग के लिए तैयार जनशक्ति विकसित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित पहलों के माध्यम से कौशल/कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दे रहा है:

(i) पीएमजीदिशा: डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) शुरू किया गया था। यह योजना सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से लागू की गई थी और यह योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हुई।

यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक के रूप में उभरी है, जिसमें देश भर में 6.39 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है (6 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले)।

तमिलनाडु राज्य में 14,07,880 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें तिरुनेलवेली जिले के 38,889 उम्मीदवार शामिल थे।

(ii) फ्यूचरस्किल्स प्राइम: फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम एमईआईटीवाई और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) की एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य भारत को एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रतिभा राष्ट्र बनाना है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, आईओटीएस, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, एआर/वीआर आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

वास्तविक रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग के परामर्श से पाठ्यक्रम विकसित किए जाते हैं। पोर्टल को उनकी योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रमाण पत्र अर्जित करने के लिए https://futureskillsprime.in/ पर ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है।

कार्यक्रम के तहत, अब तक, पोर्टल पर 27.53+ लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 17.24+ लाख उम्मीदवारों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित/प्रशिक्षित किया है। इसमें तमिलनाडु राज्य के लगभग 4 लाख उम्मीदवार शामिल हैं।

(iii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट)

नाइलिट डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम जैसे कंप्यूटर अवधारणा में जागरूकता (एसीसी), कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम (सीसीसी) आदि प्रदान करता है।

इसने डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत 43 लाख+ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षण 56 नाइलिट केंद्रों और 9000+ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण भागीदारों/सुविधा केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

एनआईईएलआईटी चेन्नई में स्थित अपने केंद्र के माध्यम से तमिलनाडु के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान कर रहा है। राज्य में डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसके 45 से अधिक सुविधा केंद्र हैं, जिनमें से 01 सुविधा केंद्र तिरुनेलवेली में स्थित हैं।

एनआईईएलआईटी चेन्नई के तहत चालू वित्त वर्ष में 1400 से अधिक उम्मीदवारों को विभिन्न डिजिटल कौशल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है

डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट

यह परियोजना 700 गांवों (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक जिले से एक) में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सौर स्ट्रीट लाइटिंग, वित्तीय समावेशन और डिजिटल सरकार-से-नागरिक और व्यवसाय-से-नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह परियोजना 31 मार्च, 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

तमिलनाडु राज्य में, तिरुनेलवेली जिले सहित 32 गांवों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था।

उक्त परियोजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस प्रकार हैं:

- शिक्षा सेवाएं: इस परियोजना के तहत प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम- बेसिक कंप्यूटर कोर्स (बीसीसी),
- कंप्यूटर कॉन्सेप्ट (सीसीसी) पर कोर्स, ताल- कौशल प्रमाण पात्रा, सूचना प्रौद्योगिकी में बेसिक कोर्स (बीसीआईटी)।
- अतिरिक्त शिक्षा: प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण, सीएडी (कंप्यूटर एडेड डिजाइन) का मूल
- स्वास्थ्य सेवाएं: टेली-स्वास्थ्य और टेली-पशु चिकित्सा परामर्श
- वित्तीय समावेशन जागरूकता कार्यक्रम
- सोलर स्ट्रीट लाइट
- ऑटोमोटिव तकनीशियन, हैंडसेट मरम्मत, फील्ड तकनीशियन - घरेलू उपकरण, और इलेक्ट्रिकल तकनीशियन में कौशल विकास

डिजिटल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा:

डिजिटल इंडिया ने भारतनेट जैसी पहल के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित देश भर में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के तेजी से विस्तार को सक्षम बनाया है। इससे देश भर में इंटरनेट की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, भारतनेट चरण- । और चरण- ।। के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क के निर्माण और शेष गैर-ग्राम पंचायतों से उनके संबंधित ग्राम पंचायतों से मांग के आधार पर कनेक्टिविटी के लिए सरकार द्वारा 04.08.2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को भी अनुमोदित किया गया है।

*****